Tc.No.: GUJHIN00722

दैनिक

क्रांति समय

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480

E-mail: krantisamay@gmail.com

सूरत, वर्ष: 1 अंक: 13 , सोमवार, 05 फरवरी 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.

ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

सार समाचार

आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

नई दिल्ली। सीलिंग के विरोध में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राजनिवास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा शासित एमसीडी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि एलजी हाउस के अंदर सीलिंग को लेकर डीडीए की बैठक भी चल रही थी।

डीडीए के निर्णय से मिलेगी राहत : गुप्ता

नई दिल्ली। भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने प्राधिकरण के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि डीडीए का यह ऐतिहासिक कदम व्यापारियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने 351 सड़कों पर चिन्ता जताते हुए कहा कि उन्हें डर है कि अब कहीं इन सड़कों पर भी सीलिंग शुरू न हो जाये। इन सड़कों को अधिसूचित करने का प्रस्ताव कई सालों से दिल्ली सरकार के पास लंबित है।

सड़क से लेकर संसद तक जारी रहेगा संघर्ष

नई दिल्ली(एजेंसी)। आप के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने सीलिंग को लेकर संसद के उच्च सदन में मामला उठाए जाने के बाद शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में संवाददाताओं से कहा कि सीलिंग के स्थायी समाधान तक संसद से सड़क तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सात लाख व्यापारियों का कारोबार तबाह हो रहा है और भाजपा तरह-तरह के बहाने बना रही है। सीलिंग के मुद्दे पर बीजेपी ड्रामा कर रही है। एमसीडी में बीजेपी, केंद्र में बीजेपी, एलजी बीजेपी शासित केंद्र सरकार के, डीडीए बीजेपी सरकार के पास। इसके बावजूद भाजपा दिल्ली की सड़कों पर जाकर व्यापारियों से झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में पार्टी के सभी राज्यसभा सदस्यों ने सीलिंग का मुद्दा उठाया।

तुषार के परिवार को मिले एक करोड़ का मुआवजा

पूर्वी दिल्ली (एजेंसी)। करावलनगर इलाके के तुकमीरपुर में नौवीं कक्षा के छात्र तुषार की स्कूल में हुई मौत को लेकर ''आप' के विधायक व पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि तुषार की मौत को हुए 24 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन अभी तक ''आप का कोई नेता व शिक्षा विभाग से कोई भी अधिकारी झांकने तक नहीं आया। कपिल मिश्रा ने कहा कि वाल्मीकि परिवार के मां-बाप की इकलौती संतान था तुषार। इस परिवार को भी एक करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। जब दिल्ली सरकार ने उत्तर प्रदेश व हरियाणा तक के परिवारों को एक-एक करोड़ का मुआवजा घोषित किया था तो इस परिवार को भी एक करोड़ रपए का मुआवजा देना चाहिए। रेयान स्कूल के मामले में तो आपने खूब बयान दिए थे, तुषार हमारी राजधानी का लाल था।

यूपी: बैंक के गार्ड की बंदूक गिरने से चली गोली, चार घायल

बुलंदशहर। नगर क्षेत्र में बैंक के गार्ड की बंदूक गिरने से गोली चल गई। घटना में 4 लोग घायल हो गए। चारों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह अंसारी रोड स्थित इलाहाबाद बैंक का एक गार्ड बैंक का कैश लेकर कार से पहुंचा। कार से उतरने के दौरान गार्ड की बंदूक जमीन पर गिर गई और उससे फायर हो गया। छर्रे लगने से सड़क से गुजरते चार लोग घटना में घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने चारों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। घटना के संबंध में समाचार लिखे जाने तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी।

शिवा के घर मे जीत को यज्ञ, जीत की ओर इंडिया की जूनियर टीम

मुरादाबाद (एजेंसी)। शिवा के घर मे जीत को यज्ञ, जीत की ओर इंडिया की जूनियर टीम 1 / 2मुरादाबाद के उभरते क्रिकेटर शिवा सिंह के घर पर सुबह से जीत के लिए यज्ञ चल रहा है। इंडिया की जूनियर टीम (अंडर 19) न्यूजीलैंड में आज ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध वर्ल्डकप का फाइनल मैच खेल रही है। मुरादाबाद... मुरादाबाद के उभरते क्रिकेटर शिवा सिंह के घर पर सुबह से जीत के लिए यज्ञ चल रहा है। इंडिया की जूनियर टीम (अंडर 19) न्यूजीलैंड में आज ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध वर्ल्डकप का फाइनल मैच खेल रही है। मुरादाबाद के स्पिनर शिवा सिंह इस फ़ाइनल में खेल रहे हैं।

वाईपीएस के ओल्ड स्टूडेंट्स से मिले कैप्टन, डिनर दिया

पटियाला। यादविंदरा पब्लिक स्कूल (वाईपीएस) के दो दिवसीय प्लेटिनम जुबली समारोह में कैप्टन अमरिंदरसिंह ने भी शिरकत की। उन्होंने पुराने यादविंदरियन और खास मेहमानों के लिए वीरवार को डिनर आयोजित कि या था। डिनर में रियासत जम्मू -कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के बेटे एवं पूर्व सांसद कर्ण सिंह, कपूरथला रियासत के पूर्व राजा ब्रिगेडि यर (रि.) सुखजीत सिंह, पूर्व कानून मंत्री और सीनियर कांग्रेसी नेता अश्वनी कुमार, इंडि यन ओलंपि क एसोसि एशन के आजीवन प्रमुख राजा रणधीर सिंह सहित 3 दर्जन के करीब खास लोग शामिल हुए। शुक्रवार को भी सीएम ने समारोह में आए लोगों को न्यू मोतीबाग पैलेस में लंच करवाया। समारोह में कैबिनेट मंत्री नवजोतसिंह सिद्धू भी शामिल हुए। बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह के पिता एवं पटियाला रियासत के आखिरी महाराजा यादविंदर सिंह ने 2 फरवरी 1948 में वाईपीएस की स्थापना की थी।

छात्र की हत्या मामले में तीन साथी हिरासत में

नई दिल्ली(एजेंसी)। करावल नगर इलाके के सादतपुर स्थित जीवन ज्योति स्कूल में नौवीं के छात्र तुषार (16) की हत्या के मामले में सीसीटीवी फुटेज और स्कूल के कुछ अन्य छात्रों के बयान के आधार पर हत्या का केस दर्ज कर पुलिस ने स्कूल में ही पढ़ने वाले तीन छात्रों को हिरासत में लिया है। आरोपी छात्र भी तुषार की कक्षा में पढ़ते हैं।

जिला पुलिस उपायुक्त डॉ. एके सिंगला ने बताया कि हिरासत में लिए गए छात्रों से पूछताछ की जा रही है, जबकि शुक्रवार को जीटीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद तुषार का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। उधर परिजनों ने शुक्रवार को उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि इस मामले में अभी एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। फिलहाल उनके बीच झगड़े और झगड़े के बाद हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस के आधिकारिक सूत्रों के हवाले मिली खबर के मुताबिक घटना बृहस्पतिवार के दिन की बताई गई है। जानकारी के अनुसार घटना के दिन तुषार का सुबह के समय स्कूल जाने के क्रम में ही आरोपी छात्रों के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। हालांकि तब किसी तरह से मामले खत्म हुआ और सभी छात्र स्कूल चले गए। स्कूल में तकरीबन सुबह दस बजे ब्रेक के दौरान भी तुषार का आरोपी छात्रों के साथ एक बार फिर से झगड़ा हो गया। जिसके बाद ब्रेक खत्म होने के दौरान जब तुषार स्कूल की टॉयलेट की तरफ गया, तो पीछे-पीछे चारों आरोपी छात्र भी उसके पास पहुंच गए।

जहां दावा किया जा रहा है कि आरोपी छात्रों ने स्कूल के टॉयलेट में ही तुषार पर बेरहमी से लात-घूंसे बरसाए, जिससे उसके नाजुक अंगों पर कड़ा प्रहार होने से वह वहीं बेसुध होकर गिर गया। हालांकि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी छात्र वहां से फरार हो गए। उधर हत्या के मामले का खुलासा होने के बाद परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर जहां पूरे मामले को दबाने का आरोप लगाया है, वहीं पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं। दरअसल स्कूल प्रशासन ने घटना के बाद तुषार की तबीयत बिगड़ जाने से बीमार होने का मामला बताया था।

करावल नगर इलाके के सादतपुर स्थित जीवन ज्योति स्कूल में नौवीं के छात्र तुषार (16) की हत्या के मामले में सीसीटीवी फुटेज और स्कूल के कुछ अन्य छात्रों के बयान के आधार पर हत्या का केस दर्ज कर पुलिस ने स्कूल में ही पढ़ने वाले तीन छात्रों को हिरासत में लिया है। आरोपी छात्र भी तुषार की कक्षा में पढ़ते हैं। जिला पुलिस उपायुक्त डॉ. एके सिंगला ने बताया कि हिरासत में लिए गए छात्रों से पूछताछ की जा रही है, जबकि शुक्रवार को जीटीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद तुषार का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। उधर परिजनों ने शुक्रवार को उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि इस मामले में अभी एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। फिलहाल उनके बीच झगड़े और झगड़े के बाद हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस के आधिकारिक सूत्रों के हवाले मिली खबर के मुताबिक घटना बृहस्पतिवार के दिन की बताई गई है।

जानकारी के अनुसार घटना के दिन तुषार का सुबह के समय स्कूल जाने के क्रम में ही आरोपी छात्रों के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। हालांकि तब किसी तरह से मामले खत्म हुआ और सभी छात्र स्कूल चले गए। स्कूल में तकरीबन सुबह दस बजे ब्रेक के दौरान भी तुषार का आरोपी छात्रों के साथ एक बार फिर से झगड़ा हो गया। जिसके बाद ब्रेक खत्म होने के दौरान जब तुषार स्कूल की टॉयलेट की तरफ गया, तो पीछे-पीछे चारों आरोपी छात्र भी उसके पास पहुंच गए। जहां दावा किया जा रहा है कि आरोपी छात्रों ने स्कूल के टॉयलेट में ही तुषार पर बेरहमी से लात-घूंसे बरसाए, जिससे उसके नाजुक अंगों पर कड़ा प्रहार होने से वह वहीं बेसुध होकर गिर गया। हालांकि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी छात्र वहां से फरार हो गए।

हत्या के मामले का खुलासा होने के बाद परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर जहां पूरे मामले को दबाने का आरोप लगाया है, वहीं पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं। दरअसल स्कूल प्रशासन ने घटना के बाद तुषार की तबीयत बिगड़ जाने से बीमार होने का मामला बताया था।

»»रिश्तेदारों में भी बांटते थे रिश्वत

कलंक कथा : कमिश्नर दिल्ली के घर में भिजवाते थे घूस का सामान,

कानपुर। घूस के इस खेल में केवल कैश ही नहीं बल्कि बेशकीमती इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ज्वैलरी और मोबाइल फोन भी चलते थे। ये गिफ्ट कमिश्नर अपने सरकारी आवास में नहीं रखते थे, बल्कि दिल्ली में डिलीवरी करवाते थे।

इन लोगों ने केवल अपने घरों को ही घूस की रकम से नहीं चमकाया, बल्कि अपने रिश्तेदारों को भी जमकर उपकृत किया।

सीबीआई रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर संसारचंद अपने सुपरीटेंडेंट्स सिंडीकेट के साथ कई अन्य बड़ी कंपनियों से बंधी घूस लेते थे। इसमें रिमझिम इस्पात लिमिटेड के योगेश अग्रवाल, सर पान मसाला के राजेश अग्रवाल, एजे सुगंधी प्राइवेट लिमिटेड के अविनाश मोदी, पुष्पराज उर्फ पम्पी जैन व अन्य कई नाम हैं। ये भी खुलासा हुआ कि रिमझिम इस्पात लिमिटेड ने संसारचंद के दिल्ली स्थित घर में सैमसंग का स्मार्ट फ्रिज घूस के तौर पर भेजा, जिसे संसारचंद की पत्नी ने रिसीव किया था। लिखापढ़ी में फ्रिज का बिल सुदेश कुमार सैनी के नाम से बनवाया गया था, ताकि संदेह की सुई न घूमे। इसी तरह

संसारचंद ने सर पान मसाला से महंगा स्मार्ट टीवी लिया। दो लाख रुपए के इस टीवी की डिलीवरी भी दिल्ली स्थित घर में की गई। इसे भी उनकी पत्नी अविनाश कौर ने रिसीव किया।

संसारचंद अपने साथ अपने रिश्तेदारों को भी घूस में मिले गिफ्ट देते थे।

इसका खुलासा एक रसीद और क्रॉस चेकिंग के दौरान हुआ। संसारचंद ने दो लाख रुपए का एक टीवी दूसरी कंपनी से बतौर 'नजराना' लिया। इस टीवी को जालंधर की फर्म रिम्पी इलेक्ट्रो वर्ल्ड से खरीदा गया था और सप्लाई भी जालंधर स्थित उनके रिश्तेदार के घर पर की गई।

गोरखपुर : सरेराह अज्ञात बादमाशों के हमले में घायल युवती ने तोड़ा दम

गोरखपुर (एजेंसी)। पैडलेगंज में सरेराह गला रेतने से घायल हुई रिसेप्शनिस्ट युवती की शनिवार की भोर में लखनऊ ले जाते समय रास्ते में बाराबंकी के पास मौत हो गई। युवती का शव लेकर परिवारीजन गोरखपुर लौटे आए और शाम को दो डॉक्टरों की टीम ने उसका पोस्टमार्टम किया। वहीं दूसरी ओर युवती की हत्या के मामले में लगी पुलिस टीम ने उसकी कॉल डिटेल के आधार पर दो लोगों को उठाया है। सहेली व अन्य से पूछताछ भी कर रही है। करीब 20 दिन तक सुनीता के साथ रहने वाली उसकी रूम पार्टनर मंशा से रूम पर आने-जाने वाले लोगों के साथ अन्य जानकारी भी पुलिस जुटा रही है। मोहल्ले में लगे सीसी कैमरे से भी पुलिस क्लू की तलाश कर रही है। घटनास्थल से पहले लगे एक सीसी कैमरे में घटना के दौरान बाइक से आते-जाते दो युवक दिखाई दे रहे हैं। उनके आने और जाने में महज तीन मिनट का अंतर है। युवती जिस समय साइकिल से कमरे पर जा रही थी उसी दौरान वह तेजी से पीछे से आए और गला रेत कर बाइक मोड़कर निकल गए। युवती की कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस को उसके एक रिश्तेदार सहित दो युवकों को उठाया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही घटना का खुलास कर लिया जाएगा।

रिश्ते में मामा लगने वाले युवक ने दिलवाई थी नौकरी

पिपराइच के चिलबिलवा नहीं व रिश्ते में मामा लगने वाले हरेन्द्र ने सुनीता को गोरखपुर में नौकरी दिलाने के साथ किराये पर कमरा भी दिलाया था। मामा का वहां काफी आना जाना था। युवती की गला रेतने की घटना के बाद पुलिस से पहले मामा ही जिला अस्पताल पहुंचा था।

दो भाई और दो बहनों में दूसरे नम्बर की थी सुनीता

सुनीत दो भाई और दो बहनों में दूसरे नम्बर की थी। बड़ी बहन मैना की शादी हो गई है। छोटे भाई लक्ष्मण नौंवी कक्षा तो गंगेश्वर सातवीं कक्षा का छात्र है। पिता हाटा में काम करता है। बीए तक पढ़ाई करने के बाद सुनीता ने घर का खर्च चलाने के लिए नौकरी शुरू की। उसने पहले हाटा में एक नर्सिंगहोम में काम किया। वहां से सात जनवरी को गोरखपुर आई। यहां बेतियाहाता में एक डॉक्टर की क्लीनिक पर रिसेप्शनिस्ट थी। रहने का कोई ठिकाना न होने पर अपनी सहली मंशा के साथ पैड़लेगंज में रूम पार्टनर थी। सहेली तीन दिन पहले रूम छोड़ चुकी है। मंशा भी चार दिन बाद कहीं और रूम लेने वाली थी।

छोटे भाई के लिए अंग्रेजी की किताब लेकर जाने वाली थी घर

शुक्रवार की शाम करीब 7.20 बजे सुनीता की अपने छोटे भाई लक्ष्मण से बात हुई थी। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे पिता ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वे लोग गरीब हैं। वह अपनी कमाई से भाइयों को पढ़ा रही थी। सुनीता की हत्या से पिता सहित पूरा परिवार सदमें हैं। उन्हें नहीं पता कि किसकी सुनीता से इतनी गहरी दुश्मनी थी कि उसने उसका बेरहमी से गला काट दिया।

भाई ने रिश्ते के मामा पर जताया है शक

सुनीता के भाई लक्ष्मण को तो अपने रिश्ते के मामा पर ही शक है। वह पोस्टमार्टम हाउस पर बार-बार हरेन्द्र का नाम ले रहा था। उसका कहना था कि कैंट पुलिस जब बहन से रात में बयान लेने की कोशिश कर रही थी तो मामा बार-बार यह कहते हुए अड़ंगा लगा रहे थे। उनका कहना था कि बयान देने की स्थिति नहीं है।

»»» डेंगू के मामलों पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार व नगर निकायों से कहा कोर्ट ने जतायी नाराजगी

भगवान के लिए अपना कर्तव्य निभाएं

नई दिल्ली(एजेंसी)। डेंगू के हालिया मामले सामने आने पर नाराजगी प्रकट करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर निगमों से कहा, ''भगवान के लिए अपना कर्तव्य निभाइए।' कोर्ट ने निगम की निष्क्रियता पर दोषारोपण करने के लिए दिल्ली सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा,''क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है।' कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से पेश वकील से पूछा,''हमेशा मामला आपके दिल्ली सरकारी बनाम केंद्र, निगम, किसी संवैधानिक प्राधिकारों के खिलाफ होता है। आप साथ मिलकर काम नहीं कर सकते क्या?' इसके बाद पीठ ने कहा कि प्राधिकारों के अपना कर्तव्य निभाने की बजाए अदालत को कचरा प्रबंधन के मुद्दे पर सक्रियता से निगरानी करनी पड़ती है और ऐसा नहीं होना, डेंगू और मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियां की एक प्रमुख वजह है। पीठ ने कहा,''हम मच्छर जनित बीमारियों के कारण दिल्ली में कोई भी मृत्यु नहीं चाहते हैं। अगर हमारा हस्तक्षेप नहीं हो तो आपको सरकार और निगम कुछ नहीं करके खुशी होती है।' कोर्ट ने कहा,''कचरा निपटान के लिए और जगहों की बजाए आप कचरा कम पैदा करने पर ध्यान दें। अन्यथा जल्द ही दिल्ली खत्म हो जाएगी और केवल कचरा फेंकने का ही स्थान रहेगा।' पीठ ने प्राधिकारों से जानना चाहा कि जनवरी में डेंगू के मामले क्यों सामने आए और कहा कि ''असहनीय अनुपात' तक इसके पहुंचने के पहले इस समस्या का समाधान करना होगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख निर्धारित की है।

जैसे शरीर बिना कहे ही अपने अधीन होता है, उसी प्रकार सज्जन लोग भी प्रेमी जनों के वश में रहते हैं -बाणभट्ट

सर्वोच्च न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट में मामलों के आवंटन के लिए रोस्टर व्यवस्था का बेशक स्वागत किया जाना चाहिए, बशत्रे इससे देश की सर्वोच्च न्यायालय में हर तरह की दुविधा मिट जाए। यह हमारे लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि हमारी न्याय व्यवस्था सुदृढ़ रहे। पिछले दिनों चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने जो सवाल उठाए, उस पर विचार भी इंसाफ घर में ही होना है, ताकि उसकी विश्वसनीयता पर कोई रत्ती भर उंगली भी न रख पाए। ऐसी खबरें थीं कि हाल में इन न्यायाधीशों और प्रधान न्यायाधीश के बीच संवाद में कुछ सुझाव दिए गए। उसके बाद ही प्रधान न्यायाधीश के आदेश से यह रोस्टर सार्वजनिक हुआ कि किन विषयों के मामले किस अदालत में जाएंगे। बेशक, इसे सार्वजनिक किए जाने से संदेह और सवालों की गुंजाइश कम हो सकती है। हालांकि कई सवाल फिर भी उठ सकते हैं। मसलन, यह रोस्टर पांच फरवरी से प्रधान न्यायाधीश के अगले आदेश तक जारी रहेगा। लेकिन चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो मामले प्रकाश में आए थे, वे पहले के हैं। इसलिए यह सवाल तो बरबस खड़ा हो जाता है कि क्या समाधान पूरा नहीं हुआ? यूं तो न्याय पण्राली की अपनी स्वायत्तता है और समाधान न हुआ हो ऐसा मानने की भी कोई वजह नहीं है। सवाल तो इसीलिए उठता है क्योंकि विवाद सार्वजनिक हो गया था। यह जिज्ञासा इसलिए भी उठती है क्योंकि इससे लोकतंत्र के अस्तित्व का सवाल जुड़ा हुआ है। इसी से यह जानने का मन होता है कि रोस्टर के तहत सारे अहम और संवेदनशील मामले प्रधान न्यायाधीश की अदालत के लिए ही क्यों रख लिये? सूचना के मुताबिक चुनाव; जनहित याचिका, संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति जैसे सभी मामले प्रधान न्यायाधीश की अदालत के विषय होंगे। यह तर्क वाजिब है कि देश की प्रथम अदालत प्रधान न्यायाधीश की है इसलिए देश में सबसे अहम मामलों की सुनवाई वहीं होनी चाहिए। लेकिन विवाद का एक पहलू तो यह भी है कि न्यायाधीशों में प्रधान न्यायाधीश पहले जरूर हैं पर सबकी पदेन गरिमा एक जैसी है। इसलिए सभी कुछ पर विचार कम-से-कम कॉलेजियम को करनी चाहिए। यह कॉलेजियम ही प्रशासनिक मामलों में भी सर्वोच्च है, यही 1993 में उस फैसले का सार था, जिससे कॉलेजियम व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। ऐसे में शायद कुछ और सुधार की दरकार है, जिस ओर माननीयों का ध्यान जरूर जाएगा।

''घृणा की विचारधारा के फैलाव'

गुजरात विधान सभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने और राजस्थान उप चुनाव में तीनों सीटों (दो संसदीय और एक विधान सभा) पर भाजपा का सूपड़ा साफ करने के बाद कांग्रेस का हौसला सातवें आसमान पर है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में 17 विपक्षी दलों की बैठक में इसे महसूस भी किया गया। बेटे राहुल गांधी को पार्टी की बागडोर सौंपने के बाद सोनिया की यह पहली बैठक थी। इसमें खासा जोर केंद्र में सत्तासीन भाजपा और उसके गठबंधन के खिलाफ एकजुटता, एक मन और एक दिल होकर जुटने का आह्वान किया गया। नि:संदेह कांग्रेस के हालिया प्रदर्शन ने उसे संजीवनी दी है। और अब पार्टी का सारा जोर न केवल भाजपा की विरोधी पार्टियों को एक साथ एक मंच पर लाना है बल्कि उनके साथ मुद्दों पर भी आम सहमति बनाने का भी है। हालांकि यह काम बेहद कठिन है, मगर भाजपा की आहिस्ता-आहिस्ता उभार से हर कोई हलकान है। स्वाभाविक रूप से विपक्षी एकता की राह में यही एकजुटता रोड़ा भी है। पूर्व के विपक्षी दलों के एक होकर लड़ने का इतिहास कमजोर ही रहा है। यही वजह है कि भाजपा को उभरने का मौका मिला। वैसे सोनिया ने बैठक में साफ तौर पर कहा कि हमें हर हाल में पूर्व के मतभेदों पर पानी डालना होगा और राष्ट्रीय स्तर पर सहमति का मसौदा तैयार करना होगा। साथ ही जिन मुद्दों को लेकर 2019 के रण में उतरना होगा, उस पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मसलन; घृणा की विचारधारा, सांप्रदायिक हिंसा व जातिगत उम्माद को खत्म करने की दिशा में कैसे मिलकर काम करना है आदि। लेकिन जिस तरह से सोनिया और राहुल दोनों ने ''घृणा की विचारधारा के फैलाव' पर अपनी बात रखी। सबसे महत्त्वपूर्ण बात जो बैठक में कही गई, वह थी राज्यों में पार्टियों का एक-दूसरे के खिलाफ लड़ाई को वहीं तक सीमित रखने की। आशय यही कि राज्यों में विवाद को आम समझ के साथ सुलझाया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर एक कंक्रीट गठबंधन के लिए यह बैठक कितना कारगर होगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। किंतु 17 विपक्षी दलों का एक साथ टेबुल पर आना आने वाले दिनों में कुछ रोमांचक और रोचक दृश्य और तर्यों के साथ देखने को जरूर मिलेगा।

सत्संग

अज्ञान मनुष्य

महाभारत न तो कभी शुरू होता और न कभी अंत, वह मनुष्य के अज्ञान के साथ चलता ही रहता है। कृष्ण ने गीता कही, उसके पहले भी वह चल रहा था; कृष्ण ने गीता पूरी की, तब भी वह चलता रहा। अज्ञान ही महाभारत है। कभी शीत, कभी गर्म, कभी प्रकट, कभी अप्रकट, लेकिन मूर्च्छा में तुम लड़ते ही रहोगे। मूर्च्छा में लड़ना ही जीवन मालूम होता है। हजार रूपों में युद्ध चल रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन तैयारी तो घर-घर में चलती है; तैयारी तो हृदय-हृदय में चलती है। युद्ध युद्ध के मैदानों पर नहीं लड़े जाते, मनुष्य के अंधकार में लड़े जाते हैं। इसे ठीक से समझ लो, अन्यथा धोखा खड़ा होता है। पहला तो धोखा यह खड़ा हो जाता है कि हम सोचने लगते हैं, महाभारत कोई बाहर का युद्ध है। महाभारत बाहर का युद्ध नहीं है। युद्ध तो भीतर का है। बाहर भी उसकी प्रतिध्वनि सुनी जाती है, बाहर भी परिणाम होते हैं। एक भी ऐसी तुम्हारे जीवन की पल-दशा नहीं है, जब तुम्हारा किसी न किसी अर्थो में संघर्ष न चल रहा हो। और जहां संघर्ष है, वहां कैसे शांति होगी? और जहां संघर्ष है, वहा कैसे समाधि फलित होगी? तुमने कभी ध्यान दिया, कितनी छोटी बातों पर तुम लड़ते हो। जैसे बातें तो बहाना हैं; लड़ना तुम चाहते हो, इसलिए कोई भी बहाना काम दे देता है। एक बड़ी प्रसिद्ध हंगेरियन कहानी है कि एक आदमी का विवाह हुआ। झगड़ैल प्रकृति का था, जैसे कि आदमी सामान्यत: होते हैं। मां-बाप ने यह सोचकर कि शायद शादी हो जाए तो यह थोड़ा कम क्रोधी हो जाए, थोड़ा प्रेम में लग जाए, जीवन में उलझ जाए तो इतना उपद्रव न करे, शादी कर दी। और आदमी झगड़ैल होते हैं, उससे ज्यादा झगड़ैल स्त्रियां होती हैं। झगड़ैल होना ही स्त्री का पूरा शास्त्र है, जिससे वह जीती है। मां-बाप लड़की के भी यही सोचते थे कि विवाह हो जाए, घर-गृहस्थी बने, बच्चा पैदा हो, सुविधा हो जाएगी। उलझ जाएगी, तो झगड़ा कम हो जाएगा। जब दो झगड़ैल व्यक्ति मिलते हैं, तो जोड़ नहीं होता गणित का; दो और दो चार, ऐसा नहीं होता, गुणनफल हो जाता है। पहली ही रात, भेंट में जो चीजें आई थीं, उनको खोलने को दोनों उत्सुक थे-पहला डब्बा हाथ में लिया। पति ने कहा यह रस्सी ऐसे न खुलेगी। मैं चाकू ले आता हूं। पत्नी ने कहा कि ठहरो, मेरे घर में भी बहुत भेंटें आती रहीं। तुमने मुझे कोई नंगे-लुच्चों के घर से आया हुआ समझा है? ऐसे सुंदर फीते कैंची से काटे जाते हैं। झगड़ा कई सालों तक चला।

चुनाव परिणाम का विश्लेषण

पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम एक अलग विश्लेषण की मांग करते हैं। लेकिन उस पर चर्चा से पहले राजस्थान के नतीजों का विश्लेषण अगले दोनों चुनाव-विधान सभा और लोक सभा-के मद्देनजर महत्त्व रखता है। चुनाव से पहले के उप चुनावों के परिणाम आम चुनाव के लिए एक संकेत के रूप में माने जाते हैं। भारतीय राजनीति के इतिहास में उप चुनाव के नतीजों को आम चुनाव में दोहराते देखा गया है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार एक बड़े जन आंदोलन के बाद बनी थी। ये किसी के लिए भी उम्मीद करना संभव नहीं था कि ढाई साल में ही प्रचंड बहुमत वाली सरकार का पतन हो जाएगा।

सतीश पेडणोकर

राजस्थान में कुछ साल पूर्व हुए विधान सभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र 21 सीटें मिली थी और लोक सभा में वह शून्य पर पहुंच गई। लेकिन पिछले चार वर्षो में चार विधान सभा सीटों पर हुए उप चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो भाजपा को मात्र एक और कांग्रेस को तीन सीटें मिली। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम एक अलग विश्लेषण की मांग करते हैं। लेकिन उस पर चर्चा से पहले राजस्थान के नतीजों का विश्लेषण अगले दोनों चुनाव-विधान सभा और लोक सभा-के मद्देनजर महत्त्व रखता है। चुनाव से पहले के उप चुनावों के परिणाम आम चुनाव के लिए एक संकेत के रूप में माने जाते हैं।

भारतीय राजनीति के इतिहास में उप चुनाव के नतीजों को आम चुनाव में दोहराते देखा गया है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार एक बड़े जन आंदोलन के बाद बनी थी। ये किसी के लिए भी उम्मीद करना संभव नहीं था कि ढाई साल में ही प्रचंड बहुमत वाली सरकार का पतन हो जाएगा। लेकिन 1980 में जनता पार्टी की पराजय से पहले इंदिरा गांधी ने कर्नाटक में चिकमंगलूर में हुए संसदीय उप चुनाव में जीत हासिल की थी। इंदिरा गांधी की वह जीत का एक नारा 1980 में उनकी पार्टी को फिर से सत्ता में बिठा दिया। राजस्थान और पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों को अपवाद के रूप में नहीं लिया जा सकता है। यह नतीजे हालात के बीच से निकले नतीजे हैं। राजस्थान में अलवर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार करण सिंह यादव ने भाजपा के जसवंत सिंह यादव को 1,56,319 वोट से हरा दिया है।

जसवंत यादव, वसुंधरा राजे सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अजमेर संसदीय क्षेत्र और विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ में हुए उप चुनाव में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की है। अजमेर लोक सभा क्षेत्र में कांग्रेस के रघु शर्मा ने भाजपा के रामस्वरूप लांबा को 84 हजार से अधिक और मांडलगढ़ विधान सभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी विवेक धाकड़ ने भाजपा उम्मीदवार शक्ति सिंह को लगभग 13 हजार वोटों से हराया। राजस्थान में लोक सभा के लिए होने वाले अगले वर्ष के चुनाव से पूर्व ही विधान सभा के लिए चुनाव होंगे। करीब सवा चार वर्ष पहले जब विधान सभा चुनाव हुए थे तब भाजपा ने दो सौ सीटों वाली विधान सभा में 163 सीटें जीती थीं। लोक सभा में तो उसे सभी 25 संसदीय सीटें मिली। विधान सभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र 21 सीटें मिली थी और लोक सभा में वह शून्य पर पहुंच गई। लेकिन पिछले चार वर्षो में चार विधान सभा सीटों पर हुए उप चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो भाजपा को मात्र एक और कांग्रेस को तीन सीटें मिली।

पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम एक अलग विश्लेषण की मांग करते हैं। लेकिन उस पर चर्चा से पहले राजस्थान के नतीजों का विश्लेषण अगले दोनों चुनाव-विधान सभा और लोक सभा-के मद्देनजर महत्त्व रखता है। राजस्थान पिछले चार वर्षो में सर्वाधिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ कई बहानों से सांप्रदायिक हमलों के लिए चर्चा में रहा है। हाल के उप चुनाव से पहले संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत के खिलाफ जिस तरह से सांप्रदायिक और जातीय उन्माद का वातावरण खड़ा हुआ, उससे भी लगा कि महारानी मुख्यमंत्री अपनी सत्ता अपनी सरकार के आर्थिक-सामाजिक विकास के कार्यक्रमों की सफलता के बूते पर लड़ने की कूव्वत नहीं रखती हैं। उसे एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है, जिससे भावनात्मक रूप से उत्तेजित होकर एक खास संप्रदाय के मतदाता भीड़ की शक्ल में मतदान केंद्रों पर टूट पड़े। लेकिन पद्मावत समाज पर सवर्ण पुरु षवादी वर्चस्व के पक्षधर के रूप में दिखने के बावजूद राजे सरकार मतदाताओं को भीड़ की शक्ल में तब्दील नहीं कर सकी। राजस्थान के चुनाव नतीजे वास्तव में गुजरात विधान सभा के लिए हुए चुनाव के नतीजों के विश्लेषण के करीब ही पहुंचती है। बल्कि ये कहा जा सकता है कि राजस्थान गुजरात की अगली कड़ी है, जो कि गुजरात चुनाव के नतीजों के विश्लेषण को पुष्ट करती है। गुजरात में प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार में गुजरात का विकास मॉडल पृष्ठभूमि में चला गया। गुजरात के सामाजिक और राजनीतिक हलचल ने भाजपा को रक्षात्मक कर दिया और वहां के मतदाताओं में सांप्रदायिक कार्ड को पांच सौ के पुराने नोट की तरह खारिज कर दिया। यह अनुभव किया जाता है कि सरकार के कामकाज से निराशा में उपजे असंतोष को सांप्रदायिक वातावरण के जरिये एक बार तो भुनाया जा सकता है, लेकिन वह बार-बार कार्ड संसदीय राजनीति में जीत का स्थायी फार्मूला नहीं बन सकता है।

राजस्थान के चुनाव नतीजों को ये मानना भी सही नहीं लगता है कि वह कांग्रेस की सक्रियता का नतीजा है। वह सत्तारूढ़ पार्टी की संस्कृति और नीतियों के खिलाफ उजपा असंतोष है। समाज में जिस तरह का राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक असंतोष है, वह स्वाभाविक रूप से सबसे बड़े विपक्ष के रूप में कांग्रेस के पास मतदाताओं को ले जाता है। जैसे मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ असंतोष भाजपा के उन मतदाताओं के बड़े हिस्से को ले गया, जो चुनाव नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। राजस्थान के नतीजों को महारानी वसुंधरा राजे और प्रथम सेवक नरेन्द्र मोदी के बीच राजनीतिक मतभेदों के रूप में भी विश्लेषित करना नतीजों की असल आवाज को अनसुना करना हो सकता है। दरअसल, संसदीय लोकतंत्र में भीड़ एक तरफ बढ़ती है और लगातार बढ़ रही है; इन नतीजों का यह संकेत है। पश्चिम बंगाल की उलबेड़िया लोक सभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने अपना कब्जा बरकरार रखा और कांग्रेस के कब्जे वाली नोआपाड़ा विधान सभा सीट पर भी उसने जीत दर्ज की। उत्तर 24 परगना जिले के नोआपाड़ा सीट से तृणमूल के सुनील सिंह को जीत मिली है। पश्चिम बंगाल में इन नतीजों का विश्लेषण इस रूप में किया जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस अपने कामकाज के कारण अपनी लोकप्रियता बनाए हुए है। लेकिन यह रु ढ़ किस्म का विश्लेषण है। वास्तव में पश्चिम बंगाल की राजनीति एक नये तरह के संक्रमण से गुजर रही है।

माकपा का लंबे समय तक शासन रहा है। मतदाताओं के बीच जो राजनीतिक विमर्श का एक ढांचा उस दौरान विकसित हुआ था, वह पूरी तरह बिखर चुका है।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने अपने पक्ष में जो मतों का समीकरण तैयार कर रखा है वह उसे तभी बरकरार रख सकती है जब कि भाजपा एक बड़े खतरे के रूप में वातावरण को निर्मित करते दिखे। तृणमूल के मतों के समीकरण और उस समीकरण के प्रति समर्पित ममता के लगातार आने वाले संदेश भाजपा के आधार को विस्तारित करने में मदद कर रहे हैं, ये नतीजे उसी के संकेत है।

चलते चलते

हबड़-दबड़

बच्चो के शोर से पलट कर देखा। मोटरसाइकिल का पहिया पांव पर चढ़ चुका था। लोग हबड़-दबड़ में सड़क पर इधर-उधर भाग रहे थे। मोटर साइकिलें गुर्रा रही थीं। मोटरसाइकिल सवार चिल्ला रहे थे। डंडों पर झंडे फड़फड़ा रहे थे-तिरंगे भी, इकरंगे भी। झंडा यात्रा निकल रही थी।धक्का लगाते हुए झंडा यात्रा आगे बढ़ी। मुंह से बरबस निकल गया-देख कर नहीं चल सकते। मोटरसाइकिल चालक ने डपटकर जवाब दिया-दीखता नहीं है, झंडा यात्रा निकल रही है। पिछली सीट पर सवार झंडाधारी इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। डंडे का झंडे वाला सिरा चेहरे के ऐन आगे नचाते हुए बोला-तू झंडे के रास्ते में कैसे आया? मोटरसाइकिलें रुक गई। झंडाधारी मोटरसाइकिल सवारों ने उतरकर घेर लिया। डंडों, झंडों और मुटंडों के घेरे

लोग हबड़-दबड़ में सड़क पर इधर-उधर भाग रहे थे। मोटर साइकिलें गुर्रा रही थीं। मोटरसाइकिल सवार चिल्ला रहे थे। डंडों पर झंडे फड़फड़ा रहे थे-तिरंगे भी, इकरंगे भी। झंडा यात्रा निकल रही थी। धक्का लगाते हुए झंडा यात्रा आगे बढ़ी। मुंह से बरबस निकल गया-देख कर नहीं चल सकते। मोटरसाइकिल चालक ने डपटकर जवाब दिया-दीखता नहीं है, झंडा यात्रा निकल रही है।

में एक ही सवाल सुनाई देता था--झंडे के रास्ते में कैसे आ गया! मैं क्यों किसी के रास्ते में आता? मैं तो अपने रास्ते जा रहा था? आप लोग ही..। उन्होंने बीच में ही बात काट दी। आप नहीं, झंडा बोल, झंडा। तू क्या कहना चाहता है, झंडा तेरे रास्ते में आ गया? तो ये रास्ता तेरा है और झंडा कहीं और से बीच में आ गया! भारत में ये झंडा बाहर का हो गया और तू यहां का! इतना भी नहीं सोचा कि भारत का झंडा भारत में नहीं फहराएगा तो क्या पाकिस्तान में फहराएगा? यह झंडा भारत में यात्रा पर नहीं जाएगा तो क्या पाकिस्तान में यात्रा पर जाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई झंडा यात्रा के रास्ते पर सवाल उठाने की? भारत का झंडा है, भारत में कहीं भी जाएगा। भारत में कहीं भी फहराया जाएगा, कासगंज में भी। जिसे परेशानी हो, खुद पाकिस्तान चला जाए या हम कब्रिस्तान पहुंचा देंगे। नारा लगाने लगे-भारत में अगर रहना होगा, झंडा-झंडा कहना होगा। पर यह तो भारत का झंडा भी नहीं है। यह तो तिरंगा नहीं इकरंगा है-सिर्फ केसरिया। अब उन्होंने केसरिया पीछे कर के तिरंगा आगे कर दिया। फिर कहने लगे-वैसे केसरिया भी तो भारत का ही झंडा है। एक से भले दो। पूछा-आगे किसे रखेंगे, तिरंगा या केसरिया? वे दर्शन पकड़कर निकल गए-आगे-पीछे से क्या है, बस झंडा ऊंचा रहना चाहिए।

फोटोग्राफी...

मित्र के कहने पर पहुंच गए अनजान आइलैंड, फिर कक्लाइम्बिंग फोटोग्राफी

यह फोटो ग्रीस की क्रिस्टल केव का है, जो कैलिम्नोज़ क्षेत्र के टेलेन्डोज़ आइलैंड पर है। इसे स्विस फोटोग्राफर डेन पेटिट्यूची ने क्लिक किया है। वे फोटोग्राफी के साथ-साथ क्लाइम्बिंग भी करते हैं। उन्होंने इस गुफा के बारे में मित्र से सुना था, इस कारण वे खुद यहां की फोटोग्राफी करना चाहते थे। फिर एक दिन वे यहां पहुंचे और गुफा के छोर पर क्लाइम्बिंग करते हुए फोटो क्लिक किया। इस आइलैंड पर स्थानीय लोगों की संख्या मात्र 54 है, लेकिन पर्यटक आते-जाते रहते हैं। डेन ने बताया कि ज़रासी लापरवाही से यहां जान जा सकती है। उनके इस फोटो को हाल ही में 500 पीएक्स के 'एडिटर्स चॉइस कलेक्शन' में चुना गया है। छठी सदी में टेलेन्डोज़ आइलैंड और कैलिम्नोज़ जमीनी तौर पर आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन भूकम्प के कारण उनके हिस्से हो गए और आज उनकी दूरी 1 किलोमीटर है।

patitucciphoto.com

ओबीओआर का विरोध

कुछ भारतीय यह दावा कर रहे थे कि ओबीओआर का विरोध करके भारत खुद को अलग-थलग कर रहा है। वास्तव में, भारत ने नियंतण्र प्रतिक्रिया को आकार देने में मदद की है-उदाहरण के तौर पर, थेरेसा मे भारत के शब्दों को प्रतिध्वनित करती हैं कि ओबीओर को पारदर्शी, खुला और नियम-आधारित होना चाहिए। टिलरसन ने इस बीच, ओबीओआर की यूरोपीय उपनिवेशवाद के साथ तुलना की है। चार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की बुनियाद है। इस अधिकार के उपयोग की खातिर सोशल मीडिया ने जो असीम अवसर नागरिकों को दिए हैं, एक दशक पूर्व इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसके माध्यम से समाज में कई क्रांतिकारी परिवर्तन भी देखे गए। लेकिन अब इस माध्यम के जरिये दुष्प्रचार, गलतफहमी और समाज में तनाव फैलाने की घटनाएं काफी हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज में इन दिनों सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने से सोशल मीडिया के दुरु पयोग की तरफ पुन: ध्यान गया है। जब भी दंगे होते हैं, उसमें अफवाह और भी आग में घी डालने का काम करते हैं। फलत: चिंगारी बुझने के बजाए और भी भड़क जाती है। कासगंज में इन अफवाहों को प्रसारित एवं प्रचारित करने का सशक्त माध्यम सोशल मीडिया बना। मसलन गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले जश्न में राजपथ पर प्रदर्शित अत्याधुनिक हथियारों को यह कहकर निर्थक बताने का प्रयास किया गया कि इसका क्या फायदा जब देश के अंदर तिरंगा लेकर चलने वाले ही असुरक्षित हों। ऐसी न जानें कितनी घृणा फैलाने वाली सामग्रियां डाली गई। किसी दूसरे देश में हुए दंगों की तस्वीरों या वीडियो को भी कासगंज का बताकर पेश किया गया, जिससे धार्मिक उन्माद को और भड़काया जा सके। हद तो तब हो गई जब सोशल मीडिया में राहुल उपाध्याय की हिंसा में मौत होने का झूठा प्रचार किया जाने लगा। ट्विटर और फेसबुक पर राहुल उपाध्याय की तस्वीरें शेयर की जाने लगी। कि दंगा को भड़काने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही थी। इन्हीं अफवाहों के कारण कासगंज में हिंसा का दौर जल्द थमने का नाम नहीं ले रहा था। यही नहीं अलीगढ़ और मैनपुरी जिले भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए।

सोशल मीडिया कंपनियों को 24 घंटों के भीतर आपत्तिजनक सामग्री हटाना होगा वरना उन पर पचास लाख यूरो से पांच करोड़ यूरो तक जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि सामग्री प्रथमदृष्टया आपत्तिजनक तो है, परंतु हिंसा भड़काने वाली नहीं है। सोशल नेटवर्क का ऐसा कोई भी प्लेटफार्म जिसके सदस्यों की संख्या 20 लाख से ज्यादा है, उन्हें शिकायत निवारण तंत्र बनाना होगा। भारत में फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरूपयोग किस प्रकार हो रहा है, इसे फेसबुक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से ही समझा जा सकता है। जुलाई से दिसम्बर 2016 की संक्षिप्त अवधि में फेसबुक ने भारत में 719 संवेदनशील अपत्तिजनक कंटेट्स को ब्लॉक किया। इसलिए आवश्यक है कि हिंसा या दंगों की दौरान सोशल मीडिया को दंगाई न बनने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 ए को असंवैधानिक घोषित किया गया, परंतु इसी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के धारा 69 ए को वैध ठहराया गया था, जिसके अंतर्गत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी सार्वजनिक उपयोग को अवरु द्ध करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर सकते हैं। भारत सरकार को समझना होगा कि हालात बिगड़ने पर इंटरनेट की सुविधा को कुछ देर केवल बंद कर देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें भी जर्मनी जैसी पहल की जरूरत है।

मुख्य कारोबार समाचार

स्लो ट्रैक पर चल रहा है रेलवे का काम, 3500 की जगह 970 KM ही बन पाई लाइनें

नई दिल्ली। आम बजट 2018-19 में रेलवे के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, लेकिन 2017-18 में की गई घोषणाएं पूरी नहीं हो पाई। पिछले साल घोषणा की गई थी कि 2017-18 में 3500 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन कमीशन की जाएंगी, लेकिन ट्रैक रिन्यूअल किया जाएगा, लेकिन नवंबर माह तक केवल 970 किलोमीटर लाइन कमीशन की गई, जबकि रेलवे स्टेशन रिडेवलमेंट के मामले में भी रेलवे का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा।

क्या थी पिछले साल की घोषणा ?

पिछले बजट में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने घोषणा की थी कि साल 2017-18 के लिए रेलवे का कुल कैपिटल और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 1 लाख 31 हजार करोड़ रुपए का होगा। इसमें से 20 हजार करोड़ रुपए रेलवे सेफ्टी के लिए दिए गए थे। इसके अलावा रेलवे को 3500 किलोमीटर रेलवे लाइन कमीशन का टारगेट दिया गया था, जो कि साल 2016-17 में 2800 किलोमीटर था। साथ ही, 25 रेलवे स्टेशन के रिडेवपलमेंट का काम शुरू करने को कहा गया था।

27 फीसदी हुआ काम

बृहस्पतिवार को जब फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने बजट डाक्यूमेंट्स जारी किया तो उसके साथ ही साल 2017-18 के बजट अनाउसमेंट की इम्पलिमिटेशन रिपोर्ट भी दी गई है। जिसके मुताबिक, रेलवे ने नवंबर 2017 तक केवल 973.57 किलोमीटर रेलवे लाइन को पैसेंजर के लिए शुरू किया। साथ ही, उम्मीद जताई गई है कि साल 2017-18 यानी मार्च 2018 तक 3500 किलोमीटर ट्रैक बन जाएगा।

नहीं हुआ स्टेशन का रिडेवलपमेंट

इसी डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि पिछले बजट में 25 रेलवे स्टेशन के रिडेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन हबीब गंज और गांधी नगर स्टेशन का काम ही शुरू हो पाया है। हालांकि रेलवे ने एक रिवाइज स्कीम शुरू की है, ताकि स्टेशन रिडेवलपमेंट का काम फास्ट ट्रैक पर आ सके।

इस बार रखा गया यह टारगेट

फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने साल 2018-19 के लिए नई घोषणा की है। इसके मुताबिक 2018-19 में 900 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जायेगी, जिसके लिए 28940 करोड़ आर्वाटित किए जाएंगे। इसी तरह 1000 किलोमीटर गेज कन्वर्शन किया जाएगा, जिसके लिए 4016 करोड़ आर्वटित किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने बड़ी संख्या में लाइन डबलिंग का टारगेट रखा गया है। साल 2018-19 में 2100 किलोमीटर लाइन डबल करने का टारगेट है, जिस पर 17359 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

भारत में iPhone की सेल 9 फीसदी गिरी, पर एप्पल का रेवेन्यू ऑलटाइम हाई पर

नई दिल्ली। बीते अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर के दौरान भारत में एप्पल iPhone की डिमांड में गिरावट दर्ज की गई है। काउंटर प्वाइंट रिसर्च के मुताबिक, पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले बीते क्वार्टर में iPhone की सेल में जहां 9 फीसदी की गिरावट रही, वहीं रेवेन्यू भी 7 फीसदी कमजोर रहा। इस दौरान iPhone ने करीब 810,000 फोन बेचे, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में उसने 890,000 स्मार्टफोन बेचे थे। हालांकि यह गिरावट तब दर्ज की गई है, जब नवंबर में iPhone X की लॉन्चिंग के बाद भारत में iPhone के ऐवरेज सेलिंग प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिली है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्मार्टफोन मार्केट के तेजी से बढ़ने की संभावनाओं के बीच iPhon की सेल में यह गिरावट देखी गई है। अगर ग्लोबल मार्केट के लिहाज से बात करें तो iPhone की सेल में हाल के कुछ सालों के दौरान 1.24 फीसदी की सालाना गिरावट देखी जा रही है।

आगे भी जारी रह सकती है गिरावट

हालांकि साल 2017 की बात करें तो भारत में आईफोन की शिपमेंट 23 फीसदी बढ़ी है। कंपनी ने जहां 2016 में 26 लाख फोन भारत में इम्पोर्ट किए थे, वहीं इस 2017 में यह करीब 32 लाख था। माना जा रहा है कि आईफोन की सेल में आगे भी गिरावट जारी रह सकती है। दरअसल 1 फरवरी को पेश बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देसी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट के करने के लिए स्मार्टफोन और उससे जुड़े कम्पोनेंट के इम्पोर्ट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ने का ऐलान किया था। नई दरें एक अप्रैल से लागू होने के बाद आईफोन की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। कीमतें बढ़ने से सेल पर असर पड़ने की पूरी संभावना है। जेटली ने फोन पर इम्पोर्ट ड्यूटी 15 फीसदी बढ़कर 20 फीसदी कर दिया है।

गरीबों को बेहतर इलाज और हॉस्पिटल इंडस्ट्री को मिलेगा बूस्ट

नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम से होगा दोहरा फायदा

एक्सपर्ट्स ने हेल्थ सेक्टर में नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम की सरहाना की है

नई दिल्ली (एजेंसी)।

बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से गरीबों के सस्ते इलाज के लिए लॉन्च की गई नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम का इंडस्ट्री स्वागत कर रही है। एक्सपर्ट मान रहे है कि नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम से दोहरा फायदा होगा, जहां एक ओर गरीबों को कम पैसों में बेहतर इलाज मिल पाएगा वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल इंडस्ट्री को भी इससे बूस्ट मिलेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र

मेडिका हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन डॉ आलोक रॉय ने बताया कि कई दशकों में पहली बार सरकार ने केंद्रीय बजट में हेल्थकेयर सेक्टर में सुधार को लेकर गंभीरता दिखाई है। जैसा कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम (स्वास्थ्य बीमा योजना) में कहा गया है कि यह 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज देगा। यह न केवल, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करेगा बल्कि यह देश में अस्पतालों के उद्धार को भी प्रोत्साहित करेगा। सरकार ने अपने इस बजट में 24 नए मेडिकल कॉलेज को लेकर भी प्रतिबद्धता जताई है जो डॉक्टरों, नर्सों और पैरामैडिकल को तैयार करेंगे, जिन्हें अच्छे से प्रशिक्षित किया जाएगा और ये देश के भावी जरूरत होंगे। इससे ग्रामीण स्वास्थ्य की देखभाल करने में मदद मिलेगी, जिसे निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों की ओर से लगभग नजरअंदाज ही किया जाता रहा है। सरकार ने बीमा प्रीमियम और हेल्थकेयर सेस पर उच्च आयकर छूट की अनुमति दी है, जो कि सरकार और व्यक्तिगत रुप से किए जाने वाले खर्चों को बढ़ावा देगी। साथ ही इससे सरकार के पास हेल्थकेयर विकास के लिए और अधिक फंड होगा जो कि सराहनीय है। डॉ रॉय देश में स्वस्थ्य नागरिकों का एक अच्छा भविष्य देखते हैं।

मायमेडिसनबॉक्स के मेंटॉर मनमोहन गुप्ता ने इस बजट को स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज अच्छा माना है। इसपर उन्होंने कहा, 'मैं निजी तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बजट 2018 के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम लाने के वादे के साथ अपने बड़े इरादे को पुष्ट किया है। अगर भारतीय अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेते हैं तो हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं जिसमें कम मेडिकल खर्चों में ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी।'

आसपास के इलाकों में 1.5 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स खोले जाएंगे जिससे कि लोगों कि पहुंच स्वास्थ्य सेवाओं तक बन सकेगी। हर परिवार में वरिष्ठ नागरिकों पर होने वाले स्वास्थ्य खर्चों की चिंता होती है। अब उन्हें राहत मिली है। ड्यूटी और काराधन में कटौती के चलते दवाइयां सस्ती होंगी। चूंकि मैं ई-फार्मेसी या हेल्थ टेक ऑनलाइन मेडिकल स्टोर के साथ जुड़ा हुआ हूं, मुझे लगता है कि डिजिटल इंडिया और ई-पेमेंट सिस्टम के जरिए उच्च मानक और गुणवत्ता की सामान्य दवाएं मुहैया कराई जा सकती है। हम मायमेडिसिनबॉक्स सरकार की ओर से की गई पहलों का समर्थन करता है। हमारा मिशन हेल्दी इंडिया- हेल्दी इंडियन है।

नोटबंदी में 15 लाख रु जमा कराने वालों की बढ़ेगी मुश्किलें, CBDT ने 2 लाख को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली (एजेंसी)।

नोटबंदी के दौरान बैंक खाते में 15 लाख या इससे ज्यादा रुपए जमा कराने वालों के लिए बुरी खबर है। दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी के बाद बैंक खातों में 15 लाख रुपए से अधिक रकम जमा करने वाले 2 लाख लोगों को नोटिस जारी किया है। CBDT के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा 15 लाख रुपए से अधिक की राशि ऐसे खातों में जमा की गई है, जिनके लिए रिटर्न भी फाइल नहीं किए गए हैं। हमनें ऐसे 1.98 लाख खातों की पहचान की है। दिसंबर और जनवरी महीने में इन खाता धारकों को नोटिस भेजे गए हैं। हालांकि अभी तक किसी ने भी नोटिस का जवाब नहीं दिया है। इन नोटिस का जवाब न देने पर विभाग द्वारा जुर्माना और मुकदमा चलाने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। चंद्रा ने आगे बताया कि 3,000 मामले पिछले तीन महीनों में दर्ज किए गए हैं। ये टैक्स चोरी, देरी से टैक्स जमा करने, इनकम छुपाने जैसे मामले हैं। उन्होंने बताया कि डिजिटलीकरण के बढ़ते दायरे को देखते हुए इनकम टैक्स विभाग भी ई-स्टेटमेंट पर ध्यान दे रहा है। चंद्रा ने बताया कि इस साल हमनें ई-असेसमेंट को ट्रायल के तौर पर शुरू किया है। तीन महीने में 60,000 ई-असेस्मेंट किए जा चुके हैं। आने वाले महीनों में यह आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है। ई-असेस्मेंट प्रक्रिया ऑनलाइन टैक्स फाइल करने और असेसमेंट की अनुमति देती है, जिससे टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होती।

अर्थव्यवस्था में मजबूती की अगुवाई करेंगे लघु व मझौले उद्योगः जेटली

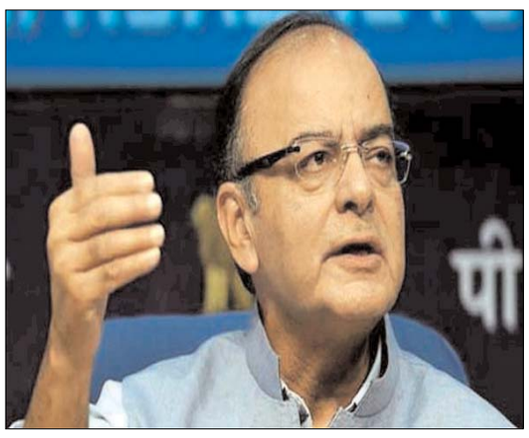

नई दिल्ली (एजेंसी)।

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की रीढ़ करार देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था में मजबूती के मौजूदा दौर की अगुवाई करेगा। जेटली ने यहां एमएसएमई के लिए अपनी तरह के पहले 'धारणा सूचकांक' क्रिसिडएक्स की शुरूआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा, 'जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है तो बीते दो साल में बहुत बड़े ढांचागत सुधारों से गुजरने के बाद अब यह भी सुदृढ़ीकरण के चरण में है। सुदृढ़ीकरण के इस चरण की अगुवाई भी एमएसएमई क्षेत्र करेगा।' जेटली ने कहा कि इस क्षेत्र की स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उठाए गए अनेक कदमों के मद्देनजर इस क्षेत्र का औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकरण तेज हुआ है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई सबसे बड़े नियोक्ता क्षेत्रों में से एक है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां लोग अपने उद्यमिता कौशल का ही प्रदर्शन नहीं करते बल्कि इस प्र?क्रिया में रोजगार प्रदाता भी बन जाते हैं।

जेटली ने कहा कि बड़ी जनसंख्या वाले देश में चाहे सरकार हो या बड़े उद्योग .. रोजगार की गुंजाइश बहुत सीमित रहती है। क्रिसिडेक्स को क्रिसिल व सिडबी ने मिलकर तैयार किया है जो आठ मानकों पर एमएसई कारोबारी धारणा का आकलन करेगा।

कमजोर मांग से चांदी 500 रुपये लुढ़की, सोना स्थिर

नयी दिल्ली। वैश्विक बाजारों के कमजोर संकेत और औद्योगिक मांग सुस्त रहने से स्थानीय सर्राफा बाजार में चांदी 500 रुपये टूटकर 39,800 रुपये प्रति किलो रह गई। हालांकि इस दौरान सोने का भाव 31,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा। सोना 99.9 प्रतिशत और 99.5 प्रतिशत शुद्धता का भाव क्रमशः 31,250 रुपये और 31,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा। गिन्नी 24,800 रुपये प्रति आठ ग्राम पर पूर्ववत रही। दिल्ली में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सीलिंग के खिलाफ कल व्यापारियों ने बंद का आयोजन किया था। सर्राफा बाजार भी बंद रहे, हालांकि आज इनमें भाव बोले गये। व्यापारियों ने कहा कि विदेशों में नरमी के रुख के साथ-साथ औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की मांग कमजोर रहना चांदी के भाव में गिरावट की मुख्य वजह रही है। राष्ट्रीय राजधानी में चांदी हाजिर 500 रुपये गिरकर 39,800 रुपये प्रति किलोग्राम और साप्ताहिक डिलीवरी आधारित भाव 835 रुपये गिरकर 38,605 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया।

वैश्विक बाजारों में न्यूयार्क में चांदी 3.63 प्रतिशत गिरकर 16.58 डालर प्रति औंस और सोने का भाव 1.22 प्रतिशत गिरकर 1,331.90 डालर प्रति औंस रह गया। चांदी सिक्का हालांकि इस दौरान लिवाली 74,000 रुपये और बिकवाली 75,000 रुपये प्रति सैकड़ा पर यथावत रही।

कुसुम योजना के तहत देश के तीन करोड़ पंपों को चलाया जाएगा सौर ऊर्जा से

कुसुम योजना पर कुल 1.40 लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी।

नई दिल्ली (एजेंसी)।

आम बजट 2018-19 में हुई तमाम घोषणाओं के बीच एक योजना ऐसी भी है, जो आने वाले दिनों में गेम चेंजर' साबित हो सकती है। इस योजना के तहत देश में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी पंपों को सोलर आधारित बनाया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की।

योजना का नाम होगा किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान (कुसुम)। योजना के तहत 2022 तक देश में तीन करोड़ पंपों को बिजली या डीजल की जगह सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। कुसुम योजना पर कुल 1.40 लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसमें केंद्र सरकार 48 हजार करोड़ रुपये योगदान करेगी, जबकि इतनी ही राशि राज्य सरकारें देंगी। किसानों को कुल लागत का सिर्फ 10 फीसद ही उठाना होगा, जबकि लगभग 45 हजार करोड़ रुपये का इंतजाम बैंक लोन से किया जाएगा।

बिजली मंत्री आरके सिंह ने बताया कि योजना का प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया गया है। पहले चरण में उन पंप को शामिल किया जाएगा जो डीजल से चल रहे हैं। इस तरह के 17.5 लाख सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा से चलाने की व्यवस्था की जाएगी। इससे डीजल की खपत कम होगी। यह योजना किसानों को दो तरह से फायदा पहुंचाएगी। एक तो उन्हें मुफ्त में सिंचाई के लिए बिजली मिलेगी और दूसरा अगर वह अतिरिक्त बिजली बना कर ग्रिड को भेजते हैं तो उसके बदले कीमत भी मिलेगी। योजना का विस्तृत प्रस्ताव सचिवों की समिति को भेजा गया है। उसके बाद कैबिनेट इसे मंजूरी देगा। इसे आगामी वित्त वर्ष से ही लागू किया जाएगा।

सरकार की योजना कहती है कि अगर देश के सभी सिंचाई पंपों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होने लगे तो न सिर्फ मौजूदा बिजली की बचत होगी बल्कि 28 हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन भी संभव होगा। कुसुम योजना के अगले चरण में सरकार किसानों को उनके खेतों के ऊपर या खेतों की मेड़ों पर सोलर पैनल लगा कर सौर ऊर्जा बनाने की छूट देगी।

यह किसानों को आय का एक अतिरिक्त जरिया देगा। साथ ही इस योजना के पूरी तरह से लागू होने से कृषि क्षेत्र में बिजली देने की मौजूदा सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि किसानों को इसकी जरूरत नहीं होगी। इसका एक असर होगा कि किसानों को मुफ्त बिजली दे कर शहरी उपभोक्ताओं से बिजली शुल्क वसूलने की मौजूदा राजनीति का भी समापन हो जाएगा।

सोनी के CFO योशिदा अब नए अध्यक्ष, हिराई का स्थान लेंगे

टोयो (एजेंसी)।

सोनी कॉर्प ने अपने मुख्य वित्त अधिकारी केनिचिरो योशिदा को आज अपना नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है। योशिदा काजुओ हिराई का स्थान लेंगे जो कंपनी के चेयरमैन बने रहेंगे। सोनी के तोक्यो मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दोनों लोग सामने आए और एक-दूसरे हाथ मिलाया। योशिदा के पास सोनी के अमेरिका परिचालन में काम करने का अनुभव है। इसके अलावा उन्होंने कंपनी के नेटवर्क, वित्त और निवेशक संबंध कारोबार की भी जिम्मेदारियां संभाली हैं। हिराई ने कहा कि योशिदा कंपनी के उस प्रगति पथ पर आगे बढ़ना जारी रखेंगे जिनकी उन्होंने शुरूआत की है। उल्लेखनीय है कि पिछले दो दशक में इस वित्त वर्ष में कंपनी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।

टाटा स्टील ने BPPL में 74 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी

नई दिल्ली (एजेंसी)।

टाटा स्टील ने जेएल पावर वेंचर्स से भुवनेश्वर पावर ञ्बीपीपीएलञ् की 74 प्रतिशत हिस्सेदारी 255 करोड़ रुपये में खरीदी है। इससे कंपनी अपने खुद के बिजली स्रोत का विस्तार कर पाएगी। पिछले साल 30 नवंबर को टाटा स्टील ने जेएल पावर वेंचर्स से बीपीपीएल के 74 प्रतिशत इक्विटी शेयर खरीदने के लिए पक्का करार किया था।

टाटा स्टील ने बंबई शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा, 'कंपनी ने एक फरवरी, 2018 को बीपीपीएल के 74 प्रतिशत इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण पूरा कर लिया है।' इस अधिग्रहण से टाटा स्टील को बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। बंबई शेयर बाजार में टाटा स्टील का शेयर आज 3.82 प्रतिशत के नुकसान से 669.70 रुपये पर बंद हुआ।

कृषि, ग्रामीण क्षेत्र में ढांचागत परियोजनाओं को आवंटन बढ़ाने से पैदा होंगे रोजगार

नई दिल्ली (एजेंसी)।

उद्योग जगत का कहना है कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में ढांचागत परियोजनाओं में 14.34 लाख करोड़ रुपये के खर्च प्रावधान से परेशानी के दौर से गुजर रहे इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उद्योग संगठन एसोचैम के अध्यक्ष संदीप जजोडिया ने एक वक्तव्य में यह बात कही। उन्होंने कहा कि 2018-19 का बजट उम्मीद के अनुरूप रहा है। इसमें समाज के उस तबके को समर्थन दिया गया है जहां इसकी सबसे अधिक जरूरत थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जानते हैं कि धन को कहां किस तरह खर्च किया जाना है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र निराशा के दौर से गुजर रहा था तथा इस क्षेत्र की ढांचागत सुविधाओं में 14.34 लाख करोड़ रुपये व्यय प्रावधान से हालात बेहतर होंगे।

जजोडिया ने कहा कि 585 ई-मंडियों में उन पर प्रतिबंधात्मक नियमों को लागू किये बिना उन्हें 22,000 कृषि उत्पाद विपणन मंडियों (एपीएमसी) से जोड़ने से न केवल किसानों को बल्कि कृषि प्रसंस्करण कार्यों में लगी कंपनियों, बड़ी खुदरा कंपनियों सहित एफएमसीजी कंपनियों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कृषि उपज के मामले में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से जुड़ी एक समस्या इसके क्रियान्वयन की है। वित्त मंत्री ने वादा किया है कि इसके लिये नीति आयोग राज्य सरकारों के साथ समन्वय बिठायेगा और सुनिश्चित करेगा कि किसानों को उनकी उपज का लागत के मुकाबले डेढ़ गुणा तक दाम मिले।

फिक्की अध्यक्ष राशेस शाह ने भी बजट को उम्मीदों के अनुरूप बताया और कहा कि इससे बड़े पैमाने पर मांग बढ़ेगी। इससे दूसरे क्षेत्रों में भी वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। एमएसएमई को वित्तीय संसाधनों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित कराने और उनके लिये कंपनी कर में कटौती का भी रोजगार और वृद्धि पर अनुकूल असर होगा और अर्थव्यवसथा के एक बड़े वर्ग को फायदा होगा। उद्योग संगठन ने बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को बड़ी घोषणा बताया है और कहा है कि इस योजना के क्रियान्वयन में आने से देश की एक तिहाई आबादी को पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा सकेगा। उद्योग संगठन ने कहा है कि प्रतिभूति कारोबार कर (एसटीटी) जारी रहने और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) फिर से शुरू करने से बाजार पर कुछ अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा लेकिन इसका लंबे समय तक बाजार पर असर नहीं रहेगा।

चीनी पर सेल लिमिट लगा सकती है सरकार, कीमतें और नीचे नहीं जाएंगी

नई दिल्ली (एजेंसी)।

चीनी की कीमतों में किसी बड़ी गिरावट की संभावना को खत्म करने के लिहाज से सरकार मिलों द्वारा चीनी की सेल पर मासिक लिमिट लगा सकती है। इससे बाजार में चीनी की ओवर सप्लाई नहीं होगी और कीमतें स्थिर रहेंगी। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आने वाले एक सप्ताह में इस तरह का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है।

15 फीसदी आई दाम में कमी

इस साल ज्यादा उत्पादन की उम्मीदों की वजह से अक्टूबर में चीनी सीजन की शुरुआत से अब तक कीमतें 15% तक कम हो गई हैं। सरकार की मंशा है कि? अब कीमतें और नीचे न जाएं। अनुमान के मुताबिक, अक्टूबर - सितंबर (2017-18) में 2.7 करोड़ टन चीनी का उत्पादन होगा। इंडिया शुगर मिल्स एसोसिएशन, इस्मा ने भी इस सीजन में प्रोडक्शन के अपने अनुमान को 10 लाख टन बढ़ाकर 2.61 करोड़ टन कर दिया है। हालांकि सरकार ने 2.49 लाख टन चीनी के उत्पादन का अनुमान जताया है। पिछले साल चीनी का उत्पादन 7 सालों के में सबसे कम 2.02 करोड़ टन था।

सरदार वल्लभभाई पटेल ब्रिज का लोकार्पण

संवाददाता, सूरत। सूरत महानगर पालिका द्वारा रविवार को तापी नदी के ऊपर स्थित अड़ाजण से अठवागेट को जोड़नेवाले सरदार वल्लभभाई ब्रिज के दोनों तरफ वाइडनिंग करने के काम में से अपस्ट्रीम साइड (अड़ाजण से अठवा की तरफ) के ब्रिज का लोकार्पण सुबह 8.00 बजे गुजरात गैस सर्कल, अड़ाजण में महापौर अस्मिता बेन शिरोया तथा बांधकाम समिति अध्यक्ष सुभाष नामदेव पाटिल के हाथों किया गया। जहां विधायक पूर्णेश मोदी सहित अन्य गण मान्य उपस्थित थे।

ग्राहकों की मांग पर प्रोसेसिंग युनिट में जॉब आर्डर की भरमार

वैवाहिक व मांगलिक आयोजनों के चलते मार्केट में कपड़ा ग्राहकी में वृद्धि

संवाददाता, सूरत। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड सहित अन्य इलाके में मांगलिक व वैवाहिक आयोजन शुरू हो गए हैं। जिससे साड़ियों व सूट के खुदरा व्यापारी सूरत से साड़ियों की जमकर खरीदी कर रहे हैं। ग्राहकों की मांग को देखते हुए कपड़ा व्यापारी प्रोसिंग मिलों में प्रिंटिंग के लिए जमकर ऑर्डर बुक कर रहे हैं। कपड़ा कारोबारी हरिवंश अरोरा ने बताया कि लग्नसरा चलने के कारण मिलों में काम करने वाले कारीगर भी अपने घर जाने की तैयारी करने लगे हैं। जबकि भेस्तान जीआईडीसी स्थित खण्डेलवाल प्रोसेसिंग मिल के भंवरलाल भाई व गोपाल रिणवा ने बताया कि खुदरा ग्राहकी होने से कपड़ा मार्केट के थोक विक्रेता कपड़ा प्रोसेसिंग के लिए बहुतायत मात्रा में ऑर्डर दे रहे हैं। वहीं काफी दिनों तक जॉब कार्य के अभाव में मिल आर्थिक रूप से बेपटरी हो गई थी। लेकिन अब ऑर्डर मिलने से प्रोसेसिंग मिलों में दिन रात प्रोसेसिंग काम शुरू है।

स्टेशन के पास बुटलेगर के अड्डे पर हमला

एक की मौत

संवाददाता, सूरत। शनिवार की देर रात सूरत रेलवे स्टेशन के समीप बुटलेगर के अड्डे पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तीक्ष्ण हथियार से हमला किए जाने से क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। यहां तक कि स्टेशन पर रखे गए वाहनों की भी तोड़फोड़ की गई और गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सूरत रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 1 पार्सल ऑफिस के समीप स्थित बुटलेगर के अड्डे पर घातक हथियारों के साथ 10 से 12 लोगों ने अचानक हमला कर दिया, जिससे चारो तरफ हड़कंप मच गया।स्टेशन पर रखे गए वाहनों की भी तोड़फोड़ की गई और गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई।

हमलाखोर इतने बे खौफ थे कि स्टेशन पर रखे गए वाहनों को भी नहीं छोड़ा और तोड़फोड़ कर दिया। इस हमला में एक कालू नामक युवक को गंभीर रूप से घायल होने से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी होने पर रेलवे पुलिस और आरपीएफ के जवान घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

भैरूजी की धूमधाम से निकली रथ यात्रा

संवाददाता, सूरत। जयश्री भीटा के भैरूजी की विशाल रथ यात्रा निकाली गई। जिसमे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर स्वयं को धन्य महसूस किया। भैरूजी की रथ यात्रा क्षेत्र के भिन्न-भिन्न स्थलों से गुजरती हुई लोगों में भक्ति के प्रति उत्साह भर रही थी। भक्तगण भैरूजी के जयकारे के साथ आगे बढ़ रहे थे। विविध क्षेत्रों से गुजरती हुई रथ यात्रा पुन: अपने स्तान पर समाप्त हुई। जहां विशाल भंडारे व महाप्रसादी के साथ इसका समापन किया गया।

पाटीदारों का केस वापस लेने का वादा सरकार नहीं निभाई तो होगा आंदोलन : लालजी पटेल

संवाददाता, सूरत। पिछले काफी समय से पाटीदारों द्वारा आरक्षण के लिए आंदोलन किया जा रहा है। इसी बीच अब एसपीजी के लालजी पटेल ने फिर से आंदोलन करने के लिए सरकार को धमकी दी है।

लालजी ने कहा कि सरकार द्वारा दिए गए वचनों को पूरा नहीं किया गया तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। सरकार ने पाटीदारों पर लगे सभी केस वापस लेने के लिए आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। इसके उपरांत सरकार द्वारा अभी तक आरक्षण के लिए सर्वे की कार्यवाही भी नहीं शुरू की गई। जिसके कारण पाटीदारों में रोष देखा जा रहा है।

एसपीजी के लालजी पटेल ने कहा कि आंदोलन के समय सरकार ने हमारे ऊपर गलत केस की है और गलत धाराएं लगाई गई हैं। ये सभी केस वापस लेने के लिए सरकार ने आश्वासन दिया था, परंतु अभी तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई। सरकार यदि अपने वादे से हटती है तो आंदोलन शुरू किया जाएगा।

एसपीजी प्रमुख ने सरकार से फिर से आंदोलन करने की दी धमकी

अहमदाबाद (ईएमएस)। सरदार पटेल ग्रुप के प्रमुख लालजी पटेल ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि पाटीदारों पर किए गए केस वापिस नहीं लेने पर फिर से आंदोलन शुरु किया जाएगा। गुजरात में पिछले काफी समय से सरदार पटेल ग्रुप द्वारा पाटीदारों को आरक्षण दिलाने के मामले में आंदोलन चल रहा है।

ट्रैफकि नियमन कराने वाले कर्मचारी पर हमला, रिक्शा चालक गिरफ्तार

संवाददाता, सूरत। सरथाणा क्षेत्र के सीमाडा चार रास्ता के पास ट्रैफिक नियमन कराने वाले टीआरबी कर्मचारी के साथ एक रिक्शा चालक ने गाली गलौज करके उसके युनिफार्म और हेलमेट को तोड़फोड़ दिया। पुलिस ने रिक्शा चालक को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सरथाणा के सीमाडा गांव दिवाली नगर घर नं. 402 प्रणाम अपार्टमेंट अंजली नगर सोसाइटी बूटभवानी के पास रहने वाले संदीप शंभूभाई जिकाद्र बतौर टीआरबी कार्यरत हैं। गत रोज संदीप सीमाडा चार रास्ता पर ट्रैफिक की ड्यूटी कर रहे थे। उसी समय दिवाली नगर अबूभाई के मकान में रहने वाला रिक्शा नं. जीजे-5-जेडजेड 5462 का चालक देवन्द्र उर्फ देव दीनानाथ शर्मा सर्कल पर आकर गलत तरीके से खड़ा हो गया। संदीप ने वहां से रिक्शा को एक तरफ लगाने को कहा। इस बात पर आरोपी ने टीआरबी संदीप से गाली गलौज करते हुए उनकी वर्दी तथा हेलमेट को जमीन पर गिराकर क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोपी देवेन्द्र को पुलिस ने गिरफ्तार करके उसके खिलाफ ट्रैफिक नियमन में व्यवधान पैदा करने का मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की है।

सनफार्मा कंपनी में लगी आग से अफरा-तफरी

संवाददाता, अंकलेश्वर। अंकलेश्वर की जीआईडीसी में स्थित सनफार्मा कंपनी में रात के समय अचानक आग लगने से आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। करीब 20 फायर ब्रिगेड की टीम स्थल पर पहुंचकर आग को काबू में किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गत रात्रि अंकलेश्वर की जीआईडीसी में स्थित सनफार्मा कंपनी में किसी कारणों से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग काफी बिकराल हो गई। घटना की जानकारी होते ही अंकलेश्वर, पानोली, झगड़िया, दहेज और सूरत की फायर टीम स्थल पर पहुंच गई। फायर की टीम को कंपनी के पास पहुंचने में व्यवधान पैदा हो गया। जिससे कुछ दूर से ही एक बिल्डिंग से पानी का फौव्वारा मारकर आग को शांत किया। शनिवार देर रात को लगी आग रविवार को काबू में आने पर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली।

400 पुलिस जवानों के साथ पुलिस ने शराब के अड्डे पर मारा छापा

अहमदाबाद (ईएमएस)। पुलिस ने 400 पुलिस जवानों के बड़े काफिले के साथ शहर के सरदारनगर-छारानगर में चल रहे देशी-विदेशी शराब के अड्डों पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में शराब को नष्ट किया। गुजरात में मद्यनिषेध का कड़ा कानून के बावजूद शराब की हेराफेरी और शराब की बिक्री की घटनाएं सामने आ रही है। ऐसे ही एक घटना प्रकाश में आई है। पुलिस ने पूर्व सूचना के आधार पर 400 पुलिस जवानों के काफिले के साथ शहर के सरदारनगर-छारानगर में छापा मारा। 2 डीएसपी, 4 एसीपी, 20 पीआई और 400 पुलिस के जवानों के काफिले के साथ पुलिस ने सर्च ओपरेशन शुरु किया।

सूरत स्टेशन की ट्रेन में एलसीबी ने 10 किलो गांजा समेत एक को पकड़ा

संवाददाता, सूरत। सूरत रेलवे स्टेशन के पास बड़े पैमाने पर गांजा और शराब की हेराफेरी किए जाने की बारदात अक्सर प्रकाश में आती रहती है। इसी दौरान रेलवे एलसीबी सूरत स्टेशन पर एक ट्रेन में से 10 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके आगे की जांच कर रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे एलसीबी गत रोज ट्रेनों में जांच अभियान शुरू की थी। इसी दौरान पोरबंदर हबड़ा ट्रेन में से 10 किलो गांजा का जखीरा मिला। पुलिस ने गांजा के साथ उड़ीसा के रहने वाले युवक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू की है।

नीलगिरी सर्कल पर 19 को छत्रपति शिवाजी जयंती, निकलेगी भव्य रैली

संवाददाता, सूरत। शहर के लिंबायत क्षेत्र में आगामी 19 फरवरी को विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की 388वीं जयती मनाई जाएगी। जिसके उपलक्ष में विशाल रैली का आयोजन किए जाने की जानकारी विहिप के पदाधिकारी ने दी। विहिप के शहर महामंत्री जोगिन्दर साहनी ने बताया कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 19 फरवरी को सुबह 10 बजे लिंबायत के नीलगिरी सर्कल पर स्थित विशाल प्रांगण में छत्रपति शिवाजी महाराज की 388वीं जयंती मनाए जाने का आयोजन किया गया है। जिसके उपलक्ष में एक विशाल रैली भी आयोजित की जाएगी। रैली शांति पूर्ण ढंग से निकल कर सम्पन्न हो, इसके लिए तमाम कार्यकर्ता कटिबद्ध हैं।

ग्रामपंचायतों के चुनाव में औसत 70 प्रतिशत हुआ वोटिंग

गांधीनगर (ईएमएस)। समग्र गुजरात में ग्राम पंचायतों के चुनाव को कही जगहों पर ग्रामजनों में उत्साह देखा गया तो कहीं निराशा भी देखनो को मिली। सुबह से मतदान केन्द्रों पर लंबी कतारें देखने को मिली तो कहीं मतदान केन्द्रों में मतदाता ही नहीं नजर आए। सभी मतदान केन्द्रों पर पुख्ता पुलिस बंदोबस्त किया गया था। सुबह आठ बजे से शुरु हुआ मतदान पांच बजे पूर्ण हुआ। दिनभर हुए शांतिपूर्ण चुनाव में औसत 70 प्रतिशत वोटिंग हुआ है। राज्य की कुल 1211 ग्रामपंचायतों के चुनाव में से 214 ग्राम पंचायत समरस घोषित की गई। ग्राम पंचायतों के चुनाव में कुल 22,036 उम्मीदवार मैदान में है। जिसमें 5928 फोर्म सरपंद पद के लिए भरे गए थे। महत्वपूर्ण बाबत यह है कि 1191 सीटों पर एक भी सदस्य ने फोर्म नहीं भरा जबकि 15 सरपंच पद रिक्त है। राज्य में 1153 ग्राम पंचायतों में चुनाव के लिए वोट डाले गए। जिसमें 1750 सदस्य निर्विरोध चुने गए जबकि 1050 ग्राम पंचायतों में अंशत: निर्विरोध चुनी गई। जिसमें 102 ग्राम पंचायत के सरपंच निर्विरोध घोषित हुए। सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत के चुनाव किसी पार्टी के चिह्न पर नहीं लड़े जाते इसके बावजूद भाजप व कांग्रेस द्वारा विभिन्न सेल व मोची का आयोजन किया गया था। 6 फरवरी को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। मध्य गुजरात की बात करें तो गांधीनगर जिले में 10 ग्राम पंचायतों में से 6 ग्राम पंचायतों में वोट डाले गए। अहमदाबाद की 13 ग्रामपंचायतों के लिए वोट डाले गए। 161 उम्मीदवारों के लिए 18,216 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। अहमदाबाद की कुल 22 में से 9 ग्राम पंचायत समरस होने पर 13 ग्राम पंचायतों के लिए वोट डाले गए जबकि वड़ोदरा में भी 190 में से 170 ग्राम पंचायतों में वोट डाले गए। जबकि 12 ग्राम पंचायत समरस घोषित की गई। छोटा उदेपुर जिले में 44 ग्राम पंचायतों में वोट डाले गए। वलसाड में शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव हुआ। जिले के तीन तहसीलों में 13 में से 12 ग्रामपंचायतों में चुनाव हुए। पारडी तहसील की वरइ ग्राम पंचायत समरस घोषित की गई। पारडी की 4 और उमरगाम की 5 ग्राम पंचायतों में मतदान हुआ। पारडी में कुल 38 और उमरगाम में 12 उम्मीदवारों का भावि ईवीएम में सील हुआ। नवसारी के 33 गांवों में शांतिपूर्ण से मतदान हुआ। मतदान को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। एक दुल्हन ने शादी से पहले वोटिंग कर अपने मताधिकार का उपयोग किया और लोगों से भी अधिक वोट करने की अपील की।

श्री महालक्ष्मी मंदिर का साल गिरह आज

पूजन के लिए मंदिर को रंग रोगन कर सजाया गया

संवाददाता, सूरत। पांडेसरा इलाके के रामेश्वर नगर प्लॉट नं 666 के सामने स्थित श्री महालक्ष्मी मंदिर का साल गिरह सोमवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए मंदिर की सफाई व रंग रोगन किया गया। सोमवार को मंदिर में पूजन अर्चन के साथ लोक मंगल की कामना की जाएगी। साल गिरह पर आयोजित महा भंडारे में काफी तादाद में भक्त महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। कार्यक्रम की सफलता के लिए उत्तम वंजी पाटिल, विलास उत्तम पाटिल, नरेश उत्तम पाटिल, निंबा बूता महाजन, अशोक महाजन, बापू महाजन, नानजी महाजन, राकेश महाजन, संदीप पाटिल, विजय उत्तम पाटिल, छोटू मंडप, गोबजी महाजन, लखन पाटिल, सुभाष मास्टर, राजू महाजन, पिंटू भाई सहित अन्य दिन रात जुटे हुए हैं।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **Tc.No. : GUJHIN00722**, E-mail: krantisamay@gmail.com